Therefore, Whitley Councils are being thought of.

Shri H. C. Heda: Why is the Government not accepting and enforcing Whitley Councils with regard to such organisations as had accepted it?

Shri Hathi: No organisation has accepted the proposal in toto; they have something to say on some condition or the other.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: 119.

Shri P. Venkatasubbaiah: 131 may also be taken up along with this.

Mr. Speaker: If it is convenient to the Minister, both may be taken up together.

हिन्दी का प्रयोग

+

*119. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० रं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बलजीत सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री चांडक :
श्री राम सहाय पांडेय :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री रा० बरुआ :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री मानवेन्द्र शाह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 जनवरी, 1965 से अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को देश की राजभाषा बनाने के सम्बन्ध में संविधान के उपबन्धों को लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या विशेष उपाय किये हैं;

(ख). क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने राज्य सरकारों को भी कोई हिदायतें भेजी हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया ।

विवरण

(क) 26 जनवरी, 1965 से अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ क्योंकि संसद् ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिये, जिनके लिये अंग्रेजी का पहले ही से प्रयोग किया जा रहा था, हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की व्यवस्था कर दी थी । कुछ साल पहले हिन्दी के क्रमिक प्रयोग के लिये सरकार द्वारा विभिन्न प्रारम्भिक उपाय हाथ में लिये गये थे । 26 जनवरी, 1965 से हिन्दी को राजभाषा के रूप में लाने के सम्बन्ध में ये विशेष उपाय किये गये—(i) भारत के राजपत्र का हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशन और (ii) (क) फार्मों के शीर्षों और रजिस्टरों का आगे से हिन्दी और अंग्रेजी में मुद्रण तथा (ख) 27 जनवरी, 1965 को सभी मंत्रालयों द्वारा हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपना लेने वाली राज्य सरकारों को एक पत्र हिन्दी में भेजने के अनुदेश ।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों को कोई हिदायतें नहीं दी गई हैं । दिनांक 13 दिसम्बर, 1964 के मुख्य-मंत्री सम्मेलन में यह तय किया गया था कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपना लेने वाली राज्य

सरकारें परस्पर हिन्दी में पत्र-व्यवहार कर सकेंगी; (ii) ऐसी रीति अपनाई जाय जिससे अहिन्दी भाषी राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे और यदि मूल पत्र हिन्दी में हो तो उसका एक प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद साथ भेजा जाय और (iii) यदि कोई राज्य केन्द्रीय सरकार को हिन्दी में लिखे तो साधारणत: अंग्रेजी अनुवाद साथ भेजा जाय ।

Anti-Hindi Demonstrations

\+

*131. **Shri P. Venkatasubbaiah:**
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri D. C. Sharma:
Shri Krishna Pal Singh:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Gulshan:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Sarjoo Pandey:
Shri Indrajit Gupta:
Shri Daji:
Shrimati Ramdulari Sinha:
Shri Yashpal Singh:
Shri H. V. Koujalgi:
Shri Hem Raj:
Shri Parashar:
Shri D. N. Tiwary:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri P. C. Borooah:
Dr. L. M. Singhvi:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there have been demonstrations in the States of Madras, Kerala and Andhra Pradesh regarding the declaration of Hindi as the Official Language; and

(b) if so, the steps taken by the Government of India in allaying the fears of the non-Hindi speaking people?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Demonstrations have been held over the question of introduction of Hindi as official language from 26th January, 1965. Hindi became official language automatically under Constitutional provisions and no formal declaration was needed.

(b) The Union Home Minister had stated at Madras on January 23 that Government had taken very great care to see that no inconvenience was caused to the non-Hindi speaking States or to non-Hindi knowing functionaries in Central Ministries and offices. He reiterated the position on January 25, while returning from Trivandrum *via* Madras. He further said that whatever would be done, would be in line with the unanimous understanding reached at the Chief Ministers' Conference held on December 13, 1964.

2. In his broadcast to the Nation on 26th January, 1965, the Home Minister explained that under Constitutional provisions, Hindi would take its place as Union official language from 26th January 1965, but people who were not conversant with Hindi would not be put to any difficulty or inconvenience as Parliament had already made provision by law for the use of English besides Hindi for all the official purposes of the Union. He also gave public assurances (a) that the process of bringing Hindi into use for the various official purposes of the Union will be so regulated and developed that it does not cause difficulty in the transaction of official work or inconvenience to people who do not know Hindi at present; (b) in determining the pace of introducing Hindi, consideration will be given, among other things, to the spread of knowledge of Hindi in non-Hindi-speaking areas, and the extent of Hindi knowledge of Government functionaries; (c) that people belonging to non-Hindi-speaking areas would not suffer in the matter of recruitment to Central services and it would not be necessary for any candidate to have